प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

पुस्तकें पढ़ने की आदत ने मुझे कम उम्र के एक लड़के से लेकर इस उम्र तक हमेशा यह एहसास कराया है कि जीवन सुंदर है।
- रस्किन बांड

प्रसिद्ध लेखक

प्रधानमंत्री मोदी की विपक्षी दलों के साथ सहयोग की पेशकश सत्तारूढ़ एनडीए के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दरअसल विशाल बहुमत के बावजूद लोकतंत्र की खूबसूरती तो इसी में निहित है कि सबको साथ लेकर चला जाए।

नई लोकसभा से उम्मीद

लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान जिस तरह से हिंदुत्व से जुड़े प्रतीकात्मक नारे लगे हैं, उससे 17वीं लोकसभा के मिजाज का पता चलता है। दरअसल इस बार भाजपा की अगुआई में न केवल एनडीए की वापसी हुई है, बल्कि उसे पिछली बार से अधिक सीटें भी मिली हैं। नई लोकसभा में अकेले भाजपा के 303 और एनडीए के 356 सांसद हैं और वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल जैसी पार्टियों का रुख उसके प्रति सकारात्मक है। इस तरह देखा जा सकता है कि मोदी सरकार को तकरीबन चार सौ सदस्यों का समर्थन हासिल है, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए कोटा से भाजपा सांसद ओम बिड़ला के प्रति गैर-एनडीए दलों द्वारा जताए गए समर्थन से पता चलता है। पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को आठ सीटें अधिक जरूर मिली हैं, लेकिन उसके सदस्यों की संख्या 52 ही है और उसे नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल सकता। सत्रहवीं लोकसभा की दलीय स्थिति बता रही है कि विपक्ष की स्थिति पिछली लोकसभा की तुलना में कमजोर ही हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की विपक्षी दलों के साथ सहयोग की पेशकश स्वागतयोग्य है। उन्होंने कहा है, 'विपक्ष के लोग नंबरों की चिंता छोड़ दें। उनका हर शब्द और उनकी भावना हमारे लिए मूल्यवान है। सांसद के रूप में हमारे लिए पक्ष, विपक्ष से अधिक निष्पक्ष की भावना महत्वपूर्ण है।' उन्हें एहसास है कि संसदीय लोकतंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए व्यापक सहमति जरूरी है। संभवतः प्रधानमंत्री को इस बात का भी एहसास है कि पिछली लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद सदन उस रूप में काम नहीं कर सका, जैसा कि उन्हें अपेक्षा थी। 16वीं लोकसभा पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली ऐसी दूसरी लोकसभा थी, जब सदन में सबसे कम काम हुआ था। वास्तव में सरकार को अब भी राज्यसभा में अहम बिलों को पारित करवाने में विपक्ष की मदद की जरूरत होगी, जहां उसके पास बहुमत नहीं है। उम्मीद है कि क्षेत्रीय दलों के सहयोग से एनडीए को अगले वर्ष तक राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि प्रधानमंत्री का संदेश विपक्ष के साथ ही उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए भी अहम है, जिन्हें बहुविध सदन की भावना को समझना होगा। विशाल बहुमत के बावजूद लोकतंत्र की खूबसूरती तो इसी में निहित है कि सबको साथ लेकर चला जाए।

एक साथ चुनाव और संघवाद

यह सच है कि मौजूदा समय में एक साथ चुनाव कराने का विचार संघवाद के लिए खतरे के रूप में दिखता है। लेकिन हमें अपनी व्यवस्था में जरूरी सुधारों से नहीं कतराना चाहिए।

आर राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार

राजग सरकार द्वारा आज 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' विषय पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है, तबसे देश भर में इस पर बहस चल रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है।

इसमें कोई शक नहीं है कि बार-बार चुनाव होने और चुनाव आचार संहिता के लागू होने से सरकार के विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। चाहे कोई इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, इसे देख सकता है। तो क्या भारत राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या अखिल भारतीय स्तर का आज कोई दूसरा बड़ा राजनीतिक दल है? 135 वर्ष पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार 2014 और 2019 में बुरी तरह चुनाव हार चुकी है। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में सिर्फ एक अखिल भारतीय पार्टी बची है? बेशक क्षेत्रीय दलों का कुकुरमुत्ते की तरह उभार हुआ है, लेकिन अपनी मातृभाषा पर जोर ही उन पर हावी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार विकास की बात करते हैं। लेकिन विकास सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं को दूर करना होगा। कुछ राज्यों में बार-बार चुनाव होते हैं, जो विकास कार्यों में बाधा डालते हैं।

भारतीय विधि आयोग ने इस पर विचार-विमर्श किया था। एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा के तहत पांच वर्ष की अवधि पर राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और पंचायतों में एकल चुनाव कराने की बात कही गई है। लेकिन एकल चुनाव प्रणाली को अपनाने में हमारे देश की बेहद जटिल और विविध राजनीतिक प्रकृति एक बड़ी चुनौती है। हमारे संविधान की संरचना एक साथ चुनाव को बढ़ावा देती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की पहली बैठक की तारीख से पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 83 (2) और 170 (1) के तहत उल्लिखित है। किसी राज्य की सांविधानिक मशीनरी के विघटन या विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 एक अपवाद के रूप में लागू किया जाता है।

पिछली बार जब देश में एक साथ चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक राजनीतिक परिदृश्य में प्रवृत्तियों और जमीनी आधार में बहुत बदलाव हुए हैं। चूंकि संविधान में एक साथ चुनाव के पक्ष में स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए गठबंधन सरकारों के उदय और बहुदलीय प्रणाली ने मौजूदा चुनावी प्रणाली को बढ़ावा दिया।

ऐसे बदलते परिदृश्यों पर चर्चा करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को चुनाव सुधारों और राजनीति में अच्छी प्रथाओं की शुरुआत की आवश्यकता है। राजनीतिक दल विभिन्न सुधारों, जैसे- राजनीतिक दलों की आय की पारदर्शिता, सक्रिय राजनीति में विभिन्न जाति समूहों और महिलाओं की भागीदारी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उपाय, विभाजनकारी राजनीति से परहेज, आदि के प्रति अनिच्छुक हैं। मतदाता उम्मीदवारों से असंतुष्ट रहते हैं। कई सारे राजनीतिक पार्टी के मैदान में रहने के बावजूद कई मतदाता नोटा का बटन दबाते हैं। वोटिंग प्रतिशत में कमी, चुनावों के दौरान गड़बड़ी की खास लहर और बेबुनियाद राजनीतिक बहस का अंतहीन सिलसिला भी चिंता के विषय हैं। यह राजनीतिक दलों की छवि पर सवाल उठाता है और लोगों के हितों को प्रभावित करता है।

आइए, हम एक राष्ट्र-एक चुनाव के फायदे और नुकसान पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि संघवाद शासन में प्रभावकारिता को बढ़ावा देता है, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक। राष्ट्र की बेहतर स्थिरता और समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि संघीय संरचना बरकरार रहे। एक साथ चुनाव कराने के विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं, मसलन-इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा, क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, संघीय संरचना में गड़बड़ी पैदा होगी, एक साथ चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों और सुरक्षा की कमी होगी तथा चेक ऐंड बैलेंस के सिस्टम में गड़बड़ी होगी।

हालांकि विभिन्न समितियों और संस्थानों की रिपोर्टों में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, जो बताते हैं कि इससे समय और ऊर्जा की बचत होगी, व्यक्तिवाद पर राष्ट्रवाद को तवज्जो मिलेगी, भ्रष्टाचार और जातिवाद की भूमिका घट जाएगी, आदर्श आचार संहिता लागू करने में सुविधा होगी और वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों, व्यक्तियों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद दिसंबर 2015 में राज्यसभा में 79 वीं रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें विभिन्न सुधारों और आचरणों का सुझाव दिया गया। इसमें यह माना गया कि आपातकाल के अलावा विधानसभाओं का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के खंड 14 एवं 15 के तहत छह महीने पहले कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने इस पर सात राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय/राज्य पार्टियों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन इस पर सर्वसहमति नहीं बन पाई।

आयोग की सबसे ताजा मसौदा रिपोर्ट विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और विशेषज्ञों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विचार जानने के बाद जारी की गई है। संविधान की संरचना को ध्यान में रखते हुए, मसौदे में संविधान और कानूनों में कम से कम संशोधन का सुझाव दिया गया है।

इसमें संविधान के अनुच्छेद 172 में संशोधन और लोकसभा के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए तीन विकल्प सुझाए हैं। एक साथ चुनाव कराने के विचार को नीति आयोग ने भी समर्थन दिया है, जो बार-बार चुनाव को एक मूलभूत समस्या बताता रहा है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में एक साथ चुनाव को शामिल किया था। इसके अलावा देश के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति भी इसका समर्थन करते हैं। कई देशों ने एक राष्ट्र-एक चुनाव की नीति को अपनाया है। लेकिन विभिन्न देशों की जलवायु और आर्थिक स्थितियां अलग-अलग हैं।

यह सच है कि मौजूदा समय में एक साथ चुनाव कराने का विचार संघवाद के लिए खतरे के रूप में दिखता है। लेकन हमें अपनी व्यवस्था में जरूरी सुधारों से नहीं कतराना चाहिए। उपर्युक्त रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के विभिन्न मॉडलों को सुझाया गया है। देश में एक साथ चुनाव कैसे लागू हो सकते हैं, यह समझने के लिए इन पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

अंतर्ध्वनि

>> अमिताभ घोष

जलवायु परिवर्तन हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है

मैं उपन्यास को एक व्यापक कल्पनाशील विफलता के लक्षण के रूप में देखता हूं। उपन्यास लेखन का एक रूप है, लेकिन मुझे लगता है कि यह विफलता पत्रकारिता सहित लेखन के सभी रूपों तक फैली हुई है। यह मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मेरे पास बहुत से युवा पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। उनमें से कुछ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बहुत दूर की चीज है, यह कहीं और हो रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि आप पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं, आपको असहनीय गर्मी और लू से गुजरना पड़ा होगा, क्या आपने इसके बारे में लिखा है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि वास्तव में किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा था। ऐसे में कोई खुद से यह सवाल पूछ सकता है कि इस विषय पर आखिर ऐसी चुप्पी क्यों है। इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के विषय पर जो कुछ भी लिखा गया, लगभग सभी गैर-कथेतर विधाओं में है। मैं उपन्यास को लेकर बहुत प्रतिबद्ध व्यक्ति हूं। अगर आप एक ऐसे माध्यम में काम कर रहे हैं, जो आपके आसपास की दुनिया को पहचानने में असमर्थ है, तो सवाल उठना लाजिमी है। इसी वजह से मैंने जलवायु परिवर्तन पर लेखों की किताब लिखी-द ग्रेट डिरेंजमेंट। मुझे हमेशा से साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद था। मैंने एक किताब भी लिखी है, जिसे कुछ लोग साइंस फिक्शन मानते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। यह दिलचस्प है कि जब लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखते हैं, तो यह लगभग स्वचालित रूप से एक अलग शैली में बदल जाता है। कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर विषय नहीं है। अगर आपकी गंभीरता नश्वर खतरों से बाहर की बात करती है, तो भला वह कैसी गंभीरता हुई? जलवायु परिवर्तन हमारे रोजमर्रा के जीवन से एकदम जुड़ा हुआ है। यह पूछना चाहिए कि मुख्यधारा के कथा साहित्य में इसे मान्यता क्यों नहीं है।

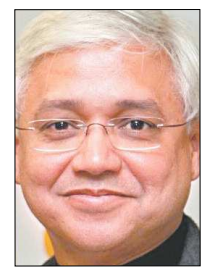

-हाल ही में ज्ञानपीठ से सम्मानित लेखक

मंजिलें और भी हैं

>> शशांक सिंह कछवाहा

पांच हजार लोगों को मिलने लगा पीने का पानी

जल संकट देश में व्यापक असर दिखा रहा है। नदियां, तालाब सूखने से भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है, आने वाले दिनों में यह गंभीर समस्या बनने वाली है। मैं मूलत: बिहार का रहने वाला हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं हीरो साइकिल में बतौर क्वालिटी मैनेजर कार्य करने लगा। एक दिन ऑफिस में एक पत्रिका पढ़ रहा था, इसी दौरान मेरी नजर जल संरक्षण से संबंधित एक लेख पर पड़ी। मैंने सोचा कि यह विचार कुछ पन्नों में सिमटने और कुछ लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के स्तर से आगे जाना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों की सहायता के साथ आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। 2015 में मैंने नौकरी छोड़ दी, और भारतीय स्टेट बैंक की यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप से जुड़ गया। इस प्रोग्राम में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास के प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है।

फेलोशिप के दौरान ही मैं 'बेयरफुट कॉलेज' नाम की संस्था के साथ अजमेर के छोटा नारायण गांव गया। वहां बात करने पर पता चला कि गांव में मौजूद तालाब सूख चुका है, जिसके चलते लोग पानी की समस्या से जूझ रहे है। इसके बाद मैंने तकरीबन सात सौ बीघे के जलक्षेत्र वाले उस सूखे पड़े तालाब पर काम करना शुरू किया। इसके तैयार होने पर आस-पास के पांच गांव के लोगों के साथ तकरीबन 5000 जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था होने की संभावना थी। स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार मिल सके, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि गांव वालों को ही इसमें काम करने का मौका दिया जाएगा। इस मुहिम के पूरा होने से अब पांच गांवों के लोगों के साथ हजारों जानवरों के पीने के पानी की आवश्यकता यहां से पूरी हो रही है, साथ ही इससे आस-पास के 50 कुओं में जल स्तर बढ़ गया है। इस बीच मेरी फेलोशिप पूरी हो गई। इसके बाद मैंने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया। तकरीबन 64 दिन तक चले इस अभियान के दौरान मैंने राजस्थान से कन्याकुमारी, रामेश्वरम और उड़ीसा तक का सफर तय किया। विभिन्न संगठनों से संपर्क कर, अलग-अलग स्कूलों-कॉलेजों में कैम्पेन कर लोगों को वर्षा जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इसके बाद झारखंड चला आया। यहां मेरी मुलाकात आदिवासी गांवों में काम कर रहे मंगेश झा से हुई। फिर हम दोनों ने मिलकर छोटा-नागपुर के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे-से गांव रसाबेदा में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। यह गांव बेकार पड़े हैंडपम्प, स्वच्छ जल स्रोत की कमी और गिरते जल स्तर जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। यहां के लोग एकमात्र जल स्रोत छूआ (जलभर) पर निर्भर हैं। छूआ धरती की सतह के नीचे चट्टानों की एक परत होती है, जहां भू-जल एकत्रित होता है और उसे निकाला जा सकता है। यहां बारिश अधिक होती है, जिसका पानी इकट्ठा करना मुश्किल है। इसलिए हम यहां के विद्यालय की छत पर पानी इकट्ठा कर वर्षा जल संरक्षण कर रहे हैं। बाकी पानी उस तरफ बहा देते हैं, जिधर हैंडपम्प हैं। इससे वहां भूमिगत पानी रिचार्ज होता है। यहां से कुछ दूर जो छूआ है, वहां बारहों महीने कम मात्रा में पानी निकलता रहता है। हम इस पानी को पाइप द्वारा विद्यालय के नजदीक बनाए गए भूमिगत टैंक में फिल्टर करके जमा करेंगे, जिसका लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे ही कई छोटे गांव, जो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, वहां इस तरह से जल संरक्षण करने के लिए जागरूक कर रहा हूं, ताकि घटते जल स्तर की समस्या गांवों के साथ ही शहरों में भी खत्म हो।

अब पांच गांवों के लोगों के साथ हजारों जानवरों के पीने के पानी की जरूरत यहां पूरी हो रही है।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित

इलेक्ट्रिक वाहन का समय आ गया

देश वास्तव में परिवहन प्रदूषण से निपटना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग को बढ़ावा देना ही होगा। दूसरी ओर इसे स्वच्छ माना जा सकता है, लेकिन यदि बिजली पैदा करने के लिए कोयले का ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा ही।

मुकुल श्रीवास्तव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने प्रदूषण पर अपनी ताजा ग्लोबल रिपोर्ट में चेताया है कि दुनिया के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में से चौदह भारत में हैं। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जहां हर साल बीस लाख से ज्यादा लोग प्रदूषित हवा की वजह से मरते हैं। पर्यावरण के मामले में भारत दुनिया के बेहद असुरक्षित देशों में है। अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी से चल रहे हैं। देश की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। शोध अध्ययन से यह पता चला है कि कम गति पर चलने वाले यातायात में विशेष रूप से जाम के दौरान जला हुआ पेट्रोल/डीजल चार से आठ गुना अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से निकले धुएं में 40 से अधिक प्रकार के प्रदूषक होते हैं।

भारत ने 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए किया था, जिसका मकसद राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, वाहन-प्रदूषण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास जैसे मुद्दों का समाधान करना था। इसके तहत पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भारत सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बनाई है। जिसमें प्रमुख है, अगले दो दशकों में इलेक्ट्रिक कारों का प्रचलन बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां, रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी (आरईसीसी) जैसी भारतीय कार निर्माता, और ओला जैसी भारतीय ऐप-आधारित परिवहन नेटवर्क कंपनियां काम कर रही हैं। भारत की सबसे बड़ी घरेलू कैब कंपनी ओला का मानना है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से ग्राहकों को कहीं ज्यादा आर्थिक लाभ होगा और उन्हें मौजूदा दर का एक तिहाई से भी कम भुगतान करना पड़ेगा। फिलहाल ईवी के परिचालन की कुल लागत का 30 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा के खर्च के रूप में होता है। लेकिन परिवहन प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या देश तैयार है? भारत में ऊर्जा क्षेत्र अभी तक इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हो सका है। ईवी उद्योग को उपयुक्त क्षमता प्रदान करने के लिए भारत को अपने सभी पावर ग्रिड और सब-स्टेशनों में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर देने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने 2022 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

लेकिन समस्या का समाधान इतना आसान नहीं है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 57,000 पेट्रोल पंपों की तुलना में महज तकरीबन 350 ईवी चार्जर हैं। जबकि चीन के पास 2016 के अंत तक दो लाख से अधिक चार्जिंग प्वाइंट थे। टाटा पावर के अनुसार, साल 2030 तक दिल्ली जैसे शहर में इस मान्यता के साथ कि शहर में दस लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हों, तो तीन लाख से अधिक फास्ट चार्जर की जरूरत पड़ेगी। इससे विद्युत व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो कि पहले से ही कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक सब्सिडी, ऊंची दर और बिजली चोरी जैसी समस्याओं से जूझ रही है।

सेंटर फॉर साइंस ऐंड रिसर्च के अनुसार, यदि भारत में 80 प्रतिशत लोग ईवी को अपनाते हैं, तो 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पहले ही बिजली की कमी झेल रहे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। देश वास्तव में परिवहन प्रदूषण से निपटना चाहता है, तो ईवी के प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना ही होगा। दूसरी ओर ईवी को स्वच्छ माना जा सकता है, लेकिन यदि बिजली पैदा करने के लिए कोयले का ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे प्रदूषण बढ़ेगा ही। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन के लिए गैर परंपरागत स्रोत से बिजली पैदा करने के बारे में सोचना होगा।

खुली खिड़की

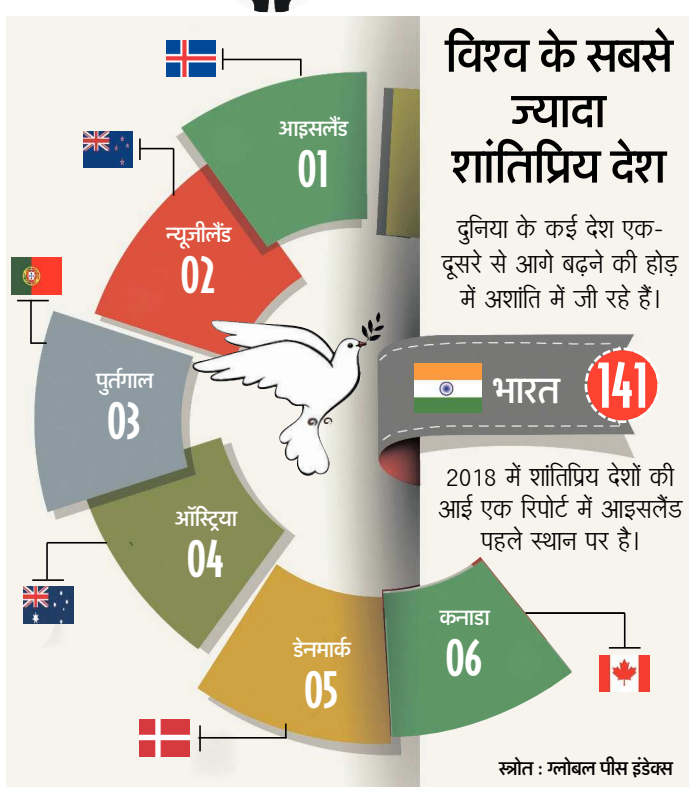

जिम्मेदारी का भाव

सत्संग

नरेंद्र (विवेकानंद के बचपन का नाम) अपने नाना के घर पर अकेले रहकर पढ़ाई करते थे। एक शाम एक व्यक्ति आया और उसने नरेंद्र से कहा, 'तत्काल घर चलो। तुम्हारे पिता का देहावसान हो गया है।' नरेंद्र तत्काल घर पहुंचे। पिता का पार्थिव शरीर कमरे में रखा था। मां और छोटे-छोटे भाई-बहन शोक में डूबे हुए थे। अगले दिन पिता का अंतिम संस्कार किया गया। नरेंद्र के पिताजी कलकत्ता के प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे। उन्होंने धन भी यथेष्ट कमाया था, परंतु अधिकतर भाग परोपकार में लगा दिया और भविष्य के लिए कुछ भी संचय नहीं किया था। मां भुवनेश्वरी देवी पर परिवार संभालने की जिम्मेदारी थी। परिवार विपन्नता के दौर से गुजर रहा था। कभी-कभी छोटे भाई-बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था जुटना भी मुश्किल था। बालक नरेंद्र गुप्त रूप से इसका पता लगा लेते थे। इस प्रकार विपन्नता में दिन बीत रहे थे। उनके रिश्तेदार बड़े ही क्रूर थे। उनमें से एक ने नरेंद्र के पैतृक मकान पर कोर्ट में दावा कर दिया। नरेंद्र ने केस की स्वयं पैरवी की और इस प्रकार के तर्क दिए कि वे केस जीत गए। जब वह बाहर आए तो विरोधी पक्ष के वकील ने उन्हें रोका और कहा 'तुम्हारे लिए वकालत उचित क्षेत्र है, इसमें काम करना चाहिए। परंतु नरेंद्र ने उनकी बात नहीं सुनी और कोर्ट से दौड़ते हुए अपनी मां के पास गए और कहा, 'मां अपना घर बच गया है।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

नटवर, साधु और हीरे का हार

यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है, जिसकी एक साधु ने इनाम पाने में मदद की।

ज्योतिरादित्य एक प्रतापी राजा था। उसे हीरे-जवाहरात का बड़ा शौक था। एक बार उसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर बेशकीमती हीरों का हार बनवाया और अपनी बेटी को भेंट किया। लेकिन कुछ ही देर बाद वह चोरी हो गया। राजा ने अपने सिपाहियों को दौड़ाया, लेकिन वह हार नहीं ढूंढ पाए। राजा ने घोषणा की कि जो भी उस हार को ढूंढकर लाएगा, उसे दस लाख रुपये दिए जाएंगे। उसी राज्य में नटवर नाम का नाई रहता था। नटवर एक दिन एक तालाब के पास से गुजर रहा था। उस तालाब से आ रही तेज रोशनी नटवर के चेहरे पर पड़ी। वह गौर से देखने लगा। किसी ने राजा का हार तालाब में फेंक दिया था। नटवर को वह हार तालाब में दिख गया। वह तालाब में घुसकर हार टटोलने लगा। नटवर को हार दिख रहा था, पर जैसे ही वह उसे निकालने लगता, हार गायब हो जाता। इस बार नटवर ने उस कीचड़ वाले गंदे पानी में डुबकी लगा दी और काफी देर तक पानी में हाथ घुमाता रहा। हार अब भी नहीं मिला। नटवर ऊपर से नीचे तक कीचड़ से नहा चुका था। तभी वहां से एक साधु गुजरे और उसे ऐसे कीचड़ में खड़े देख हंसने लगे। वह तालाब से बाहर निकला और चिल्लाकर साधु से बोला, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? मैंने यह काम एक मकसद से किया है, और वह पूरा हो गया, तो मैं तुम पर भी ऐसे ही हंसूंगा। साधु बोले, तुम्हारा मकसद मुझे साफ दिख रहा है। तुम्हारा उद्देश्य तो ठीक है, पर दिशा गलत है। तुम्हें अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए स्तर थोड़ा ऊपर उठाना होगा। तभी उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और देखा, वह हार पानी में नहीं, बल्कि ऊपर पेड़ की डाल पर लटक रहा था। पानी में तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब था। जिस साधु को उसने दुश्मन समझा, उसने उसकी मदद की।

हमें हर किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, कई लोग हमारे सहायक भी होते हैं।